भारत सरकार
पंचायती राज मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2822
दिनांक 10.03.2026 को उत्तरार्थ

ग्रामीण आबादी वाली भूमि का मानचित्रण

†2822. श्री विष्णु दत्त शर्मा:

क्या **पंचायती राज मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ग्रामीण आबादी वाले क्षेत्रों का मानचित्रण करने अैर संपत्ति कार्ड प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर स्वामित्व योजना लागू कर रही हे ताकि परिसंपत्ति सुरक्षा और ऋण पहुंच में सुधार हो सके और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या खजुराहो लोक सभा क्षेत्र के कटनी, पन्ना जिलों और खजुराहो शहर की ग्राम पंचायतों ने मानचित्रण और संपत्ति कार्ड वितरण का कार्य पूरा कर लिया है और इससे लाभान्वित परिवारों की संख्या कितनी है;

(ग) क्या इन जिलों के लाभार्थियों ने ऋण प्राप्त करने, उद्यम शुरू करने या सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए संपत्ति काडों का उपयोग किया है और यदि हां, तो तर संबंधी ब्यौरा कया है;

(घ) क्या स्थानीय स्तर पर कवरेज या ऋण प्राप्ति की दर कम है और यदि हां, तो इसके क्या कारण है और इस संबंध में उठाए गए उपचारात्मक कदमों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या इन जिलों में ग्रामीण गरीबों की आय बढ़ाने के लिए स्वामित्व योजना के परिणामों को आजीविका कार्यक्रमों के साथ एकीकृत करने का कोई प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पंचायती राज मंत्री

(श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह)

(क) जी हां, पंचायती राज मंत्रालय ग्रामीण आबादी वाले क्षेत्रों का मानचित्रण करने और ग्रामीण परिवारों को संपत्ति कार्ड प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर स्वामित्व योजना लागू कर रहा है। 5 मार्च 2026 तक, 3.44 लाख अधिसूचित गांवों में से 3.29 लाख गांवों में ड्रोन सर्वेक्षण पूरा हो चुका है और 1.87 लाख गांवों के लिए 3.10 करोड़ संपत्ति कार्ड तैयार किए गए हैं।

(ख) मंत्रालय के पास उपलब्ध जानकारी के अनुसार, पन्ना जिले में सभी 937 अधिसूचित गांवों में ड्रोन सर्वेक्षण पूरा हो चुका है और 728 गांवों के लिए 1,16,854 संपत्ति कार्ड तैयार किए जा चुके हैं। कटनी जिले में, सभी 840 अधिसूचित गांवों में ड्रोन सर्वेक्षण पूरा हो चुका है और 839 गांवों के लिए 1,51,634 संपत्ति कार्ड तैयार किए जा चुके हैं। खजुराहो शहर, जो खजुराहो लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत आता है, नगर पंचायत क्षेत्र के रूप में शासित है। स्वामित्व योजना के प्रावधानों के अनुसार, शहरी आबादी क्षेत्रों का सर्वेक्षण शामिल नहीं है; इसलिए, खजुराहो शहर में स्वामित्व योजना लागूनहीं की गई हैं।

(ग) स्वामित्व योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण इलाकों में संपत्ति के मालिकों को अधिकारों का रिकॉर्ड देना है। मंत्रालय के पास उपलब्ध जानकारी के अनुसार, कटनी जिले में 59 लाभार्थियों ने स्वामित्व संपत्ति कार्ड का उपयोग करके 2.37 करोड़ रुपये के बैंक ऋण का लाभ उठाया है। पन्ना जिले में किसी भी लाभार्थी द्वारा कोई ऋण नहीं लिया गया है।

(घ) स्वामित्व योजना के तहत लाभार्थियों को लाभ प्राप्त करने में सक्षम बनाने के लिए स्थानीय स्तर पर व्यापक जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। राज्य स्तर पर राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति के साथ नियमित बातचीत की जा रही है।

(ङ) राज्य से प्राप्त विभिन्न सफलता की कहानियाँ दर्शाती हैं कि स्वामित्व संपत्ति कार्ड ग्रामीण लोगों की आजीविका में सुधार करने में सहायक है। ग्रामीण गरीबों की आय बढ़ाने के लिए स्वामित्व योजना का योगदान महत्वपूर्णहै।

****